हिन्दी दैनिक
लखनऊ जंक्शन
RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com
वर्ष: 11 अंक: 99 लखनऊ, शनिवार 22 नवंबर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

52 देशों के प्रतिनिधि पहुचे लखनऊ, मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन

कहा, भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह 9 बजे सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के बाद न्यायविदों की परिचर्चा प्रारंभ होगी। सायंकालीन सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि और मेयर सुषमा खर्कवाल विशिष्ट अतिथि शमिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यहां सिटी मांटेसरी स्कूल (सीएमएस) के तत्वावधान में आयोजित विश्व के प्रधान न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए कहा कि भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अतिथियों के आगमन पर राज्य सरकार और यहां के लोगों की ओर से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए योगी ने कहा, यह भारत की न केवल एक भावना रही है, बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं, जिसे उसके संकट के समय में भारत ने शरण न दी हो, भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। योगी ने कहा, आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया भर से जुड़े न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं तो इस अवसर पर सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृतियों को नमन करता हूं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।''मुख्यमंत्री ने कहा, ''उन्होंने ही वैश्विक एकता, शांति और न्याय के लिए मुख्य न्यायाधीशों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की। योगी ने कहा, हमें इस बात को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि वास्तव में दुनिया की समस्या क्या है और कहीं न कहीं जब हम इसके तह में जाते हैं तो लगता है कि एक दूसरे के बीच में ''संवाद'' नहीं है या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इसे बाधित किया गया है। उन्होंने कहा, ''यह सम्मेलन वास्तव में दुनिया भर की मानवता के लिए संवाद का एक माध्यम है, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, दुनिया में जहां अशांति है, जहां पर अराजकता है, जहां वर्चस्व को

लेकर एक दूसरे के संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर शिक्षा, वहां पर विकास अपने आप में बेमानी सी दिखती है और उन स्थितियों में हम सबको विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किये जाने की जरूरत है, हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं सीएमएस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों के सम्मेलन से पूर्व 52 देशों से आए विदेशी मेहमानों ने आगरा स्थित ताजमहल का भ्रमण किया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विभिन्न देशों से आए 160 से अधिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एवं कानूनविदों का लखनऊ में स्वागत किया। सीएमएस में आयोजित 'विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' में प्रतिभाग करने देर शाम सभी अतिथि लखनऊ पहुंचे। विदेशी मेहमानों के स्वागत में राजाजीपुरम प्रथम कैंपस में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ की विरासत अमन, चौन और सुख–शांति की रही है। दुनिया भर से आए न्यायविद जब एकता और शांति का संदेश विश्व को देंगे, तो यह लखनऊवासियों के लिए गर्व का विषय होगा। क्रोएशिया के पूर्व राष्ट्रपति स्टीपन मेसिक, लेसोथो के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. पकालिथा बी. मोसिलिली, घाना की संसद के सभापति अल्बन किंग्सफोर्ड सुमाना बैगबीन, एंटीगुआ और बरबूडा संसद के अध्यक्ष आस्बर्ट आर. फ्रेडरिक समेत कई देशों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश प्रमुख रूप से शामिल रहे।

ईडी ने कोयला माफिया के खिलाफ कसा शिकंजा

झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगह की छापेमारी

एजेंसी

रांची/कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ धन शोधन मामले में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के अंतर्गत दोनों राज्यों में 40 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। एजेंसी झारखंड में कोयला चोरी और तस्करी से संबंधित जांच के तहत लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।सूत्रों के अनुसार, अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल बी सिंह और अमर मंडल के नाम वाली संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच के तहत दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में लगभग 24 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

एनआईए के इनपुट पर 10 से ज्यादा डॉक्टरों से एटीएस ने की पूछताछ, बहराइच सहित इन जिलों में छापे

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। जैश–ए–मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल द्वारा दिल्ली में बम विस्फोट की घटना अंजाम देने के मामले की जांच एनआईए के

सुपुर्द करने के बाद यूपी में भी कार्रवाई तेज होती जा रही है। एनआईए के इनपुट पर यूपी एटीएस ने शुक्रवार को आधा दर्जन जिलों के 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की है। ये सभी मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन और डॉ. आदिल के संपर्क में थे। फिलहाल एटीएस ने किसी को भी हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों की मानें तो जिन जिलों के डॉक्टरों से पूछताछ की गई है, उनमें बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। खासकर मुरादाबाद में तीन डॉक्टरों की गतिविधियां संदिग्ध मिलने पर गहनता से जांच की जा रही है। तीनों को राजधानी स्थित एटीएस मुख्यालय भी बुलाया गया है। तीनों डॉ. मुजम्मिल और डॉ. आदिल के संपर्क में थे और दिल्ली की घटना के बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया था। तीनों की लोकेशन बीते माह फरीदाबाद में मिली है, जिसकी वजह से उन पर शक गहराता जा रहा है। एनआईए को सौंपे सुबूत वहीं दूसरी ओर एटीएस ने डॉ. शाहीन और डॉ. परवेज के घर से बरामद सुबूतों को एनआईए के हवाले कर दिया है। दरअसल, एनआईए ने अभी तक इस प्रकरण को लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। एनआईए द्वारा जांच टेकओवर करने के बाद केस प्रॉपर्टी को उनके सुपुर्द किया गया है। जल्द ही सहारनपुर में चिन्हित वाहनों और डॉ. परवेज की कार के बारे में भी एनआईए को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बता दें कि डॉ. परवेज की कार जब्त करने के बाद मड़ियांव थाने भेज दी गई थी। सूत्रों की मानें तो एनआईए की एक टीम जल्द यूपी में आकर नए सिरे से पड़ताल करेगी। फिलहाल राजधानी स्थित एनआईए थाने के अधिकारी यूपी एटीएस के साथ मिलकर जांच कर रही है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने किया भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन, कहा– विरासत की समझ को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी

हैदराबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को हैदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा जताया कि इस कार्यक्रम से पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक विरासत की समझ को बढ़ावा देगा। राष्ट्रपति निलयम में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कि भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण में बीते साल प्रतिभागियों को उत्तर भारत के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि जो इस नौ दिनों के कार्यक्रम में शामिल होंगे, वे सभी हस्तकला, संगीत, नृत्य, साहित्य के साथ

गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के भोजन से रूबरू होंगे। हस्तशिल्प कलाकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने वाले कौशल का सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है, जब लोग यहां आएंगे और अलग–अलग राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखेंगे तो उन्हें अनुभव होगा कि भारत की कला और परंपरा कितने महान हैं। उन्होंने कहा कि देशवासी, खासकर युवा अपनी सभ्यता और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के साथ शिमला, हैदराबाद और देहरादून के राष्ट्रपति निवास लोगों के लिए खुले हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जगहों पर जाएं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से परिचित हों। उन्होंने कहा, ष्मैं राष्ट्रपति भवन को जनता का भवन मानती हूं। यह राष्ट्र का भवन है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों से जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष मार्च में दक्षिणी राज्यों पर केंद्रित विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले देशवासियों को एक–दूसरे को समझने में सक्षम बनाएंगे।

मशीनों से नहीं, सैनिको के कौशल से जीती जाती है जंग, CAATS परेड में बोले लेफ्टिनेंट जनरल सेठ

एजेंसी

मुंबई। भारतीय सेना के साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने साफ कहा कि असली युद्ध मशीनें नहीं, बल्कि उन्हें चलाने वाले सैनिकों के साहस, कौशल और फैसला लेने की क्षमता से जीते जाते हैं। नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (सीएएटीएस) में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने बदलती युद्ध परिस्थितियों और उसकी नई चुनौतियों पर गहरी बात रखी। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिसमें प्रिसिशन अटैक, हाई–टेंपो ऑपरेशन, मल्टी–डोमेन इंटीग्रेशन और लगातार चुनौतीपूर्ण एयरस्पेस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आर्मी एविएशन सेना को तीसरा और बेहद प्रभावी आयाम देता है, जो उसे तेज, सटीक और निर्णायक शक्तियों से लैस बनाता है। इसी क्षमता के कारण आज एविएशन फोर्स सेना का एक प्रमुख कॉम्बैट मल्टीप्लायर बन चुका है। आर्मी एविएशन की भूमिका और नई तकनीकें उन्होंने कहा कि मानव–संचालित और मानव–रहित प्लेटफॉर्म का संयुक्त उपयोग सेना को रिकॉनाइसेंस, सर्विलांस, लिफ्ट, अटैक और प्रिसिशन एंगेजमेंट जैसी क्षमताएं प्रदान करता है।

दक्षिण अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी, जी–20 लीडर्स समिट में लेंगे हिस्सा

एजेंसी

जोहानिसबर्ग। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को तीन दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी20 शिखर सम्मेलन से इतर छठे आईबीएसए (भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वह वसुधैव कुटुंबकम तथा 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' की भावना के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग रवाना होने से पूर्व पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने

जा रहा हूं। यह शिखर सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसका आयोजन अफ्रीका में हो रहा है। इसमें अनेक वैश्विक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। कई नेताओं से भी करेंगे मुलाकात शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री के जोहानिसबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। वहां वह छठे आईबीएसए (भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तीन सत्रों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के तीनों सत्रों को संबोधित करेंगे। यह जी20 समूह का लगातार चौथा शिखर सम्मेलन होगा, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से पहले जी20 की अध्यक्षताएं क्रमशः ब्राजील (2024), भारत (2023) और इंडोनेशिया (2022) द्वारा की गई थीं। जी20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट से गौतम गंभीर को मिली बड़ी राहत, कोविड दवाओं के अवैध भंडारण की शिकायत खारिज

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनके एक संगठन और अन्य के खिलाफ महामारी के दौरान कोविड–19 दवाओं के 'अवैध' भंडारण और वितरण के लिए आपराधिक शिकायत खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, ''आपराधिक शिकायत रद्द की जाती है।'' उच्च न्यायालय ने यह आदेश उस अर्जी पर दिया जिसमें गंभीर, उनकी पत्नी, मां और संगठन के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी और आपराधिक शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, की पूजा–अर्चना

एजेंसी

तिरुमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा–अर्चना की। राष्ट्रपति ने सबसे पहले श्री वराहस्वामी मंदिर का दौरा किया। उसके बाद तिरुमला मंदिर के महाद्वारम पहुंचीं, जहां तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अध्यक्ष बी. आर. नायडू और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, ''राष्ट्रपति ने अपने परिवार के सदस्यों और अधिकारियों के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में पूजा की।

एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है, बिहार ने देश में घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश दिया : शाह

एजेंसी

कच्छ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी नीत राजग की जीत देश में घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश है क्योंकि नागरिक कभी भी उन दलों का समर्थन नहीं करेंगे जो ऐसे अवैध प्रवासियों का समर्थन करते हैं। शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें। शाह ने एसआईआर को मतदाता सूची का ''शुद्धिकरण बताया। वह गुजरात के कच्छ जिले के भुज में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हीरक जयंती (61वें स्थापना दिवस) समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ रोकने में लगा हुआ है। घुसपैठ रोकना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हालांकि, कुछ राजनीतिक दल सरकार के घुसपैठ विरोधी अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष ने एसआईआर पर आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि इससे लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शाह ने कहा, ''वे चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर और मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस देश से हर एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। यह हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा, ''देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा, यह निर्णय केवल भारत के नागरिक ही ले सकते हैं। घुसपैठियों को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित करने और हमारे लोकतांत्रिक निर्णयों को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि एसआईआर भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है और हर नागरिक को इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''मैं उन राजनीतिक दलों को भी आगाह करना चाहता हूं जो इन घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। बिहार चुनाव देश की जनता का जनादेश था। और यह जनादेश हमारे देश में घुसपैठियों की मौजूदगी के खिलाफ है। शाह ने कहा, ''मतदाता सूची में घुसपैठियों की जगह सुनिश्चित करने के लिए काम करने वाले दलों को पता होना चाहिए कि देश की जनता ऐसे इरादों का कभी समर्थन नहीं करेगी।श्श बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह के दौरान शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत भारत बहुत जल्द नक्सली समस्या से मुक्त हो जाएगा।

राजनाथ सिंह बोले-कई देश खुलेआम इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहे; फैसले बिना भेदभाव के होने चाहिए

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। सिटी मांटेसरी स्कूल में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। सीएम योगी ने सुबह सम्मेलन का उद्घाटन किया। शाम को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, कई देश खुलेआम इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कई देश अपने कानून बनाकर दुनिया पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय और शांति अब सिर्फ आदर्श नहीं रहे। बल्कि दुनिया के बने रहने की नींव बन गए हैं। इसलिए, यह समय यूनाइटेड नेशंस की बुराई करने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का है। हमारा मानना है कि यूएन में सुधार करके दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है। यूएन में रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। फैसले बिना

किसी भेदभाव के होने चाहिए और पावर–शेयरिंग सच्ची होनी चाहिए। तभी यह संस्था एक बार फिर अपना असली मकसद पूरा कर सकती है। आज, जब हमारे सामने एक टूटी–फूटी दुनिया है, जहां कई झगड़े साथ–साथ हो रहे हैं, तो यह और भी साफ हो जाता है कि दुनिया को भारत के सिविलाइजेशनल नजरिए से बहुत कुछ सीखना है। वर्चस्व को लेकर एक–दूसरे की संप्रभुता हड़पने की होड़ सीएम योगी ने कहा, शिक्षा में इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे बस्ते के बोझ से बोझिल न हों। दुनिया में जहां अशांति और अराजकता है। जहां वर्चस्व को लेकर एक–दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य की बात अपने आप में एक बेमानी सी दिखती है। इसके लेकर हम सभी को यह सोचना चाहिए कि किस स्तर तक की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं।

संपादकीय

चुनौतियों वाली पारी

आखिरकार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। जदयू सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता का एक नया कार्यकाल शुरू कर दिया। यद्यपि हालिया चुनाव में भाजपा ने जदयू से ज्यादा सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपस्थिति दर्ज करायी है, लेकिन इसके बावजूद चार कम सीट जीतने वाले जदयू के 74 वर्षीय दिग्गज को मुख्यमंत्री बने रहने देना ही बेहतर समझा है। वहीं सहयोगी दल भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के उपमुख्यमंत्री पद बरकरार रहे। निस्संदेह, नीतीश का पिछला कार्यकाल उतार–चढ़ाव भरा रहा था। उन्होंने पहले भाजपा के साथ सरकार बनायी और मनभेद के चलते महागठबंधन में शामिल हुए। फिर पलटी लेकर भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद बिहार की जनता ने उनकी इस उलट–पलट को माफ ही कर दिया। संभवतरू उनकी इस अपील पर वोट दिया कि यह उनकी आखिरी पारी है। जनता ने उनके नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के स्थायित्व पर भरोसा जताया। शायद बिहार की जनता जंगल राज के दुरूस्वप्न को नहीं भूली है। एक बात तो तय है कि राज्य की जनता ने तमाम किंतु–परंतुओं के बावजूद बिहार के भविष्य के लिये उन्हें बेहतर माना है। यही वजह है कि रिकॉर्ड दसवीं बार शपथ लेने वाले नीतीश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुशासन के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक अनुभवी प्रशासक बताया है। लेकिन राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि भाजपा कब तक छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? विपक्ष को संदेह है कि नीतीश शायद ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्हें आशंका है कि भाजपा किसी न किसी स्तर पर बिहार में पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, जहां भाजपा ने पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में उन्हें हटाकर देवेंद्र फड़नवीस को कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों का तर्क है कि भाजपा के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए एनडीए सरकार को सहारा देने के लिये भाजपा को नीतीश के समर्थन की जरूरत बनी रहेगी। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जदयू अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिये बेहतर स्थिति में है। बहरहाल, नीतीश की तात्कालिक प्राथमिकताएं बेरोजगारी दूर करने और पलायन पर अंकुश लगाने की होनी चाहिए। हकीकत यह है कि राज्य में रोजगार संकट के चलते बिहार के तीन घरों में से दो का एक सदस्य दूसरे राज्य में काम करने को मजबूर है। साथ ही नीतीश को सरकार बनाने में भरपूर समर्थन देने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रमुख चुनावी वायदे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जदयू मजबूत और अक्षुण्ण बना रहे। यह अवश्यंभावी है कि भाजपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उन्हें सतर्क बनाए रखेगी। भाजपा के मन में यह कसक जरूर रहेगी कि सबसे बड़े दल के रूप में उदय होने पर भी पार्टी बिहार में अब तक अपनी सरकार नहीं बना पायी है। ऐसे में नीतीश को बाहरी विपक्षी से तो नहीं, गठबंधन के दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जूझना पड़ेगा। वहीं प्रचंड बहुमत देने पर जनता की उम्मीदें भी उफान पर रहेंगी। राजग द्वारा चुनाव के दौरान तमाम वायदे किए गए थे, लेकिन राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर इन सब वायदों को पूरा करना आसान न होगा। वहीं दूसरी ओर नीतीश के सामने उनकी सेहत और बढ़ती उम्र को लेकर भी चुनौती पैदा हो सकती है। जिसको लेकर विपक्ष पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगातार हमलावर बना रहा है। साथ ही बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं को दस हजार रुपये लगातार दे पाना भी परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं गठबंधन सरकार के लिए चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन द्वारा किए गए मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली,मुफ्त इलाज,सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने तथा पचास लाख पक्के मकान के वायदे को हकीकत में बदलने को वित्तीय संसाधन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

राशिफल

मेष :– काफी दिनों से अवरोधित कोई हल होने के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किया गया प्रयत्न सार्थक होगा। रोजगार में लाभकारी अवसर मिलेंगे।
बृषभ :– भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी। अतः व्यवहार कुशल बने। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी।
मिथुन :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में जाया न करें। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें और परिवार के अनुकूल चलें।
कर्क :– नये व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। संवेदनशील शरीर ग्रहां की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। पुरानी घटनाओं से मन को कष्ट संभव।
सिंह :– नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। महत्वपूर्ण कायरें में लापरवाही कतई न करें।
कन्या :– जीवनसाथी के स्वास्य के प्रति सचेत रहें। नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। नये क्षेत्रों में प्रयास से लाभ संभव। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ होगा। संबंधियों के सहयोग से कठिनाइयां दूर होंगी।
तुला :– भविष्य को लेकर मन नकारात्मक आशंकाओं से प्रभावी रहेगा। प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।
वृश्चिक :– रोजगार संबंधी कुछ नयी योजनाओं पर मन केंद्रित होगा। किसी कार्य में सफलता से उत्साह में वृद्धि होगी। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें। भौतिक सुख में वृद्धि होगी।
धनु :– अपनी बातूनी कला का लाभ उठाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। परिश्रम से आर्थिक लाभ का योग है। समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी।
मकर :– बीती बातों को सोचने के बजाय वर्तमान में जीने की चेष्ठा करें। जरूरत से ज्यादा बोलना व्यक्तित्व पर कुप्रभावी होगा। अतरू इसे सुधारें। नीरस स्वभाववश रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में असमर्थ होंगे।
कुंभ :– सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। थोड़ा संयमी व धैर्यवान बने। भाग्य से प्राप्त सभी स्थितियों के मध्य समझौतावादी रवैया अपनायें। कुछ नई व्यस्तताएं सामने आएंगी। आलस्य कतई न करें।
मीनः– कुछ व्यासायिक कारणों से घर से दूर रहना पड़ सकता है। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त–मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा।

वैश्विक व्यापार में रुपये की नई दस्तक

रुपये के वैश्वीकरण की दिशा में भारत के बढ़ते कदम

–डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत आज उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण केंद्र बन रहा है और इसी आकांक्षा के साथ वह अपनी मुद्राकृभारतीय रुपयेकृको अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अधिक स्वीकार्य बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। बदलते भू–राजनीतिक वातावरण, डॉलर–निर्भरता से जुड़ी अनिश्चितताओं तथा बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था के उभार ने यह अवसर प्रदान किया है कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ाए। इसी संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत और इसे अनेक देशों के साथ लागू करने की कोशिश रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत बनाने वाली निर्णायक पहल बनकर उभरी है। रुपये के प्रसार के पीछे कई प्रेरक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, क्योंकि डॉलर आधारित भुगतान तंत्र अनेक बार राजनीतिक तनाव, प्रतिबंधों और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के समय जोखिम पैदा करता है। रूसदृयूक्रेन संघर्ष के बाद भारत ने अनुभव किया कि डॉलर आधारित तंत्र के कारण कई लेनदेन बाधित हो जाते हैं और व्यापार प्रभावित होता है। यदि व्यापार सीधे स्थानीय मुद्राओं में हो, तो भुगतान अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर भी अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। साथ ही, कई देश अब अपने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे डॉलर–केंद्रित व्यवस्था धीरे–धीरे परिवर्तित हो रही है। भारत भी इस परिवर्तनशील प्रवृत्ति का स्वाभाविक हिस्सा है। भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और बढ़ते व्यापारिक संबंध भी रुपये–आधारित निपटान की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, भारतदृरूस व्यापार पिछले दो दशकों में कई गुना बढ़ा है, परन्तु इस व्यापार में रुपये का उपयोग सीमित है। मुद्रा–आधारित विकल्प बढ़ने से न केवल व्यापार गति पकड़ता है बल्कि भारतीय निर्यातकों को विनिमय दर के उतारदृचढ़ाव और हेजिंग लागत से भी राहत मिलती है। दीर्घकाल में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा भारत की आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का संकेत भी बनती है। भारत के 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 1 खरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में यह एक अनिवार्य कदम माना जा रहा है। हालाँकि, रुपये के वैश्वीकरण के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं। अनेक देशों को अभी भी डॉलर या अपनी स्थानीय मुद्रा अधिक स्थिर विकल्प लगती है। कुछ देशों को रुपये की विनिमय दर की स्थिरता पर भरोसा कम है। व्यापारिक साझेदारों के साथ मूल्य–वृद्धि आधारित वस्तुओं का आदानदृप्रदान सीमित होने से भी रुपये के व्यापक प्रयोग की संभावना घटती है। भारतीय निर्यातकों में भी रुपये आधारित निपटान के प्रति जागरूकता कम है, जिसके कारण वे इस विकल्प का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अंतरराष्ट्रीय भुगतान और संदेश प्रणाली की सीमित परस्पर संपर्कता भी रुपये की स्वीकार्यता को धीमा करती है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में देश पारंपरिक वैश्वीकरण संदेश तंत्र पर निर्भर हैं। इन चुनौतियों के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत अब संयुक्त रूप से सहमत देशों के साथ सीधे रुपये में व्यापार कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मॉरीशस और मालदीव के साथ हुए समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम होगा बल्कि बैंकिंग लागत और भुगतान समय में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने पड़ोसी देशों के बैंक एवं नागरिकों को रुपये में ऋण देने की अनुमति देकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया है। भारत ने अपने त्वरित भुगतान तंत्र को कई देशों से जोड़कर एक नई वित्तीय संपर्क व्यवस्था विकसित की है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्वरित भुगतान तंत्र का जुड़ना छोटे व्यापारियों, पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए तत्काल भुगतान को सरल बनाता है, जिससे रुपये की उपयोगिता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही भारत अपनी वित्तीय संदेश प्रणाली को भी साझेदार देशों की प्रणालियों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे परंपरागत वैश्विक संदेश तंत्र पर निर्भरता कम होगी। यह व्यवस्था भुगतान प्रक्रिया को राजनीतिक तनावों से सुरक्षित रखेगी और रुपये की विश्वसनीयता बढ़ाएगी। समग्र रूप से रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक आकांक्षा का आधार है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, डिजिटल भुगतान संपर्क, द्विपक्षीय वित्तीय संवाद और निर्यातकों की जागरूकताकृये सभी घटक मिलकर रुपये को वैश्विक व्यापार में अधिक उपयोगी और स्वीकृत मुद्रा बना सकते हैं। चुनौतियाँ अवश्य हैं, परंतु बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के पास अवसर भी विशाल है। यदि भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करे, भुगतान तंत्र को सरल बनाए और रुपये की स्थिरता को मजबूत करे, तो आने वाले वर्षों में रुपये की वैश्विक भूमिका निश्चित रूप से विस्तार पाएगी।

सुख का मापदण्ड और भारतीय यथार्थ

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट की सीमाएँ और भारत में सहानुभूति–ढाँचे की अनिवार्यता

–डॉ. सत्यवान सौरभ

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट हर वर्ष किसी देश की सुख–संतुष्टि का आकलन प्रस्तुत करती है। किंतु भारत जैसे विशाल, विविध और सांस्कृतिक रूप से जटिल देश के लिए यह रिपोर्ट कई बार उस यथार्थ को उजागर नहीं कर पाती जो समाज के भीतर गहरे स्तर पर मौजूद है। भारत की रैंकिंग अक्सर सौ से ऊपर दिखाई देती है, जबकि इसी अवधि में भारत ने स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, संरचनात्मक सुधारों और गरीबी कमी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। यह विरोधाभास एक नैसर्गिक प्रश्न खड़ा करता हैकृक्या किसी देश के "सुख" को केवल सर्वेक्षण–आधारित दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? और क्या यह मापन भारतीय जीवन–मूल्यों और सामाजिक वास्तविकताओं को पकड़ने में सक्षम है? विश्व हैपीनेस रिपोर्ट का आधार मुख्यतः स्व–आकलन है। सर्वेक्षणकर्ता उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि वे जीवन को दस–स्तरीय सीढ़ी में कहाँ रखते हैं। यह "सीढ़ी–संबंधी मूल्यांकन" पश्चिमी मनोविज्ञान में प्रयुक्त उस विचार पर आधारित है जिसमें सुख को व्यक्तिगत प्राप्तियों और परिस्थितियों के आधार पर मापा जाता है। परन्तु भारतीय समाज में सुख की अवधारणा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामुदायिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक आयामों से भी गहराई से जुड़ी होती है। भारतीय संस्कृति में संतोष, कर्तव्य, परस्पर सहायता, संबंधों की स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन भी सुख का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। इसलिए जब एक भारतीय उत्तरदाता से पूछा जाता है कि वह दस में से अपने जीवन को कितने अंक देगा, तो उसके भीतर कई सांस्कृतिक कारक सक्रिय होते हैं कृविनम्रता, शांत–स्वीकृति, परिस्थिति को भाग्य–नियति से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति, या समाज में शिकायत दिखाने से बचना। इसके परिणामस्वरूप अनेक भारतीय अपने जीवन को कम अंक दे सकते हैं, भले ही वे वस्तुतः अनेक स्तरों पर बेहतर स्थिति में हों। सर्वेक्षण का नमूना आकार भी भारत के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले, शहरी और ग्रामीण विविधताओं से भरे देश के लिए मात्र लगभग एक हज़ार लोगों के उत्तर पर आधारित निष्कर्ष असंतुलित हो सकते हैं। भारतीय समाज क्षेत्रीय, भाषायी, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों पर अत्यंत विषम है; एक छोटे नमूने का उपयोग करके उस विविधता का प्रतिनिधित्व संभव नहीं। एक जिले के ग्रामीण किसान की जीवन–संतुष्टि की अवधारणा दिल्ली के शहरी पेशेवर व्यक्ति से भिन्न हो सकती है। फिर भी, दोनों को समान पैमाने पर रखकर किसी राष्ट्रीय "सुख–अंक" की व्याख्या करना वैज्ञानिक रूप से सीमित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में प्रयुक्त सुख की अवधारणा भी सांस्कृतिक पक्षपात से प्रभावित है। पश्चिमी ढाँचा सुख को भौतिक उपलब्धियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष संतुष्टि से जोड़ता है, जबकि भारतीय समाज में अनेक बार सुख का अर्थ कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना, भावनात्मक सहारा, सामुदायिक सहयोग या आध्यात्मिक शांति से भी जुड़ा होता है। यह अंतर सर्वेक्षणकर्ता की भाषा, शैली, शब्दों और उत्तरदाता के मनोभाव को प्रभावित करता है। अक्सर यह देखा गया है कि भारत के ग्रामीण या अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में उत्तरदाता "जीवन के अंक" को किसी ऐसे प्रश्न की तरह स्वीकार करते हैं जिसमें शिकायत या असंतोष दिखाना उचित नहीं लगता। इसी वजह से कई भारतीय वास्तविक अनुभव होने के बावजूद संतुष्टि को अपेक्षाकृत कम आंकते हैं, जिससे परिणाम और अधिक विकृत होते हैं। इसके विपरीत, भारत ने बीते वर्षों में सामाजिक कल्याण में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। करोड़ों लोगों तक निःशुल्क खाद्यान्न पहुँचाना, सर्वजन स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों में विस्तार, शिक्षा तथा महिला–शिशु पोषण कार्यक्रमों में बढोत्तरीकृये सब समग्र जीवन–गुणवत्ता को बढ़ाने वाले उपाय रहे हैं। किन्तु अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें इन संकेतकों को केवल सीमित रूप से जोड़ती हैं, क्योंकि उनका मूल केंद्र "अनुभूत संतुष्टि" पर आधारित है, न कि "वस्तुनिष्ठ कल्याण" पर। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठ रूप से बेहतर होती सुविधाएँ भी रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से उजागर नहीं हो पातीं। भारत में गरीबी में कमी और स्वास्थ्य–सेवाओं की पहुँच में वृद्धि ने जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाया है, परन्तु सुख–सर्वेक्षण इस सकारात्मक परिवर्तन को मापने में अक्षम रहते हैं। ऐसे में, प्रश्न यह उठता है कि भारत को अपने भीतर ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे समाज अधिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित, सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित बन सके। इसका उत्तर "सहानुभूति संरचना"कृ एक व्यापक सामाजिक ढाँचा है जिसमें राज्य, समाज, संस्थान और समुदाय मिलकर नागरिकों को भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सहारा, संवाद और सहायता प्रदान करें। इस ढाँचे का पहला स्तंभ मानसिक–स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। भारत में मानसिक–स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कई भ्रम और कलंक मौजूद हैं। लोग सहायता लेने में संकोच करते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा ढाँचे में मानसिक स्वास्थ्य की अनुपस्थिति समस्या को बढ़ाती है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित परामर्शदाता हों, दूरभाष–आधारित सेवाएँ व्यापक हों और विद्यालयों–कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध हो, तो समाज में भावनात्मक असुरक्षा घट सकती है।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समुदाय–आधारित सहयोग है। भारतीय संस्कृति में पड़ोस, परिवार और सामाजिक संबंधों की शक्ति अत्यधिक रही है, परन्तु शहरीकरण और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के कारण यह संरचना कमजोर हो रही है। यदि स्थानीय समुदायों में संवाद–चक्र, सहारा–समूह, वरिष्ठ नागरिक सहायता–केंद्र, महिलाओं के लिए सुरक्षित समुदाय–स्थल और युवाओं के लिए साझा सहयोग मंच विकसित किए जाएँ, तो सामाजिक एकांत कम हो सकता है। सहानुभूति तभी विकसित होती है जब लोग एक–दूसरे के जीवन में उपस्थिति का अनुभव करें। सहानुभूति संरचना का तीसरा स्तंभ कार्यस्थल है। कार्यस्थलों पर तनाव, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य–दबाव और असुरक्षा बढ़ रही है, जिसके चलते कर्मचारियों का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। यदि संस्थान संवेदनशील नीति अपनाएँकृकार्य अवधि में लचीलापन, परामर्श सेवाएँ, साथी–सहयोग कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण में सहानुभूति–आधारित व्यवहारकृतो यह वातावरण को स्वस्थ बना सकता है। एक सहानुभूतिपूर्ण संस्थागत संस्कृति न केवल कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाती है। चौथा आयाम विद्यालयों में भावनात्मक शिक्षा का है। बच्चों में सहानुभूति, अहिंसक संवाद, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोगात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि बच्चे अपनी भावनाएँ समझना, व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखें, तो समाज भविष्य में अधिक संवेदनशील बनेगा। शैक्षणिक ढाँचा केवल परीक्षा–आधारित न रहकर जीवन–आधारित होना चाहिए। पाँचवाँ पक्ष तकनीकी सहारा है। यदि तकनीक का उपयोग मानसिक–स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग के लिए किया जाएकृजैसे परामर्श ऐप, संकट में सहायता, छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल संवाद केंद्रकृतो यह सहानुभूति संरचना को व्यापक बना सकता है। तकनीक का जिम्मेदार उपयोग सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकता है, बशर्ते उसकी निगरानी और नैतिकता मजबूत हो। अंततः, राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में भी सहानुभूति की आवश्यकता है। जब सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, परिवहन, सुरक्षा और न्याय–प्रणाली में कार्यरत लोग नागरिकों के प्रति अधिक करुणामय व्यवहार अपनाएँ, तो नागरिक–राज्य संबंध और भी मजबूत होते हैं। जनता की समस्याओं को सुनना, सम्मान देना और समाधान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इस प्रकार विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग उसे केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय एक अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। यह अवसर भारतीय समाज को यह विचार करने का मार्ग देता है कि कैसे हम "सुख" को केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक भरोसा, संवेदनशील संवाद और मानसिक–स्वास्थ्य संरचना के रूप में विकसित कर सकते हैं। रिपोर्ट की पद्धति में चाहे जितनी सीमाएँ हों, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज किस दिशा में जाए। भारत यदि अपनी पारंपरिक सामुदायिक शक्ति को आधुनिक सामाजिक–कल्याण ढाँचे के साथ जोड़ दे, तो सहानुभूति–आधारित विकास की एक नई धारा स्थापित हो सकती है, जो वास्तविक सुख को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

आतंकवाद की ओर जा रहे हैं –कुछ डाक्टर

–जूलियो रिबैरो

मैडिसिन के डाक्टर हमेशा से हमारे कामों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं, जिनकी इस दुनिया में हर इंसान तारीफ करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी डाक्टर की जरूरत न पड़ी हो। डाक्टरों को नेक इंसान माना जाता है जो दूसरे इंसानों को जिंदा और ठीक रखने की फिक्र करते हैं। 10 नवंबर,2025 को दिल्ली में लाल किले के पास मैट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके में 13 आदमी मारे गए और कई आदमी और औरतें घायल हो गई, यह न सिर्फ हमारी मजबूत सरकार के लिए बल्कि हमारे देश के आम लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान में मौजूद जैश–ए–मोहम्मद से जुड़े एक टैरर मॉड्यूल का पता चला। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग डाक्टर हैं। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आम आदमी ऐसे टैरर मॉड्यूल की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें एक डाक्टर भी शामिल हो। अब उसे बताया जा रहा है कि इस खास मॉड्यूल में ज्यादातर डाक्टर हैं जो सभी इस्लाम को मानते हैं लेकिन जम्मू–कश्मीर, हरियाणा और बंगाल जैसे अलग–अलग राज्यों से हैं। सिर्फ सबसे होशियार स्टूडैंट ही मैडिकल कॉलेज में सीट पक्की कर सकते हैं। पढ़ाई साढ़े 5 साल की होती है और अगर स्टूडैंट मैडिसिन की किसी भी ब्रांच में स्पैशलाइज करना चाहता है तो उसे 2 साल या उससे ज्यादा और लगेंगे,

जिसके बाद जरूरी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी होगी। जिन डॉक्टरों ने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल ऐसी जिंदगी की तैयारी में बिताए हैं जो दूसरों को जिंदा रहने में मदद करती है, वे अपना मकसद क्यों छोड़कर सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को मैसेज देने के लिए बेगुनाह लोगों को मारने और घायल करने पर उतर आएं? इसका जवाब पिछले कुछ सालों में खोजे गए दूसरे टैररिस्ट मॉड्यूल में मिल सकता है। अभिनव भारत एक अकेला मॉड्यूल था जो हैरानी की बात है कि ज्यादातर कम्युनिटी में घुसा हुआ था, जिसे महाराष्ट्र के एंटी–टैररिस्ट स्क्वॉड ने खोजा था। पॉलिटिकल फील्ड में फायदेमंद पोजीशन वाले लोगों में भी जो गहरा गुस्सा था, उसे हमें अपने मन की आंखों में, उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इस समीकरण के शिकार थे। जब भारत के इकलौते मुस्लिम–बहुल राज्य को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और उन लोगों ने उसे कमतर दर्जा दिया, जिन्हें उसका सैक्युलर और बराबरी के रैंक में स्वागत करना चाहिए था, उसे बुरी तरह याद दिलाया गया कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा तो दुश्मनी और नफरत को पनपने के लिए जमीन तैयार हो गई। मोदी–शाह की जोड़ी का मजबूत गवर्नेंस मॉड्यूल जम्मू–कश्मीर में अपने तख्तापलट की शेखी बघारता रहा। राज्य में और ज्यादा सैनिक और पैरा–मिलिट्री भेजी गई, इस उम्मीद में कि बॉर्डर पार से आतंकवाद और कश्मीरियों के बीच अलगाववादी तत्व बेअसर हो जाएंगे। शुरू में ऐसा सरप्राइज फैक्टर की वजह से हुआ। राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुश्किल और हमेशा रहने वाली हिंदू–मुस्लिम समस्या को बहुत सोच–समझकर और बारीकी से सुलझाया था। उन्होंने पूर्व रॉ चीफ ए.एस. दुलत पर भरोसा किया, जिन्होंने फारूख अब्दुल्ला के साथ पक्की दोस्ती की थी। अब्दुल्ला परिवार ही काफी हद तक कश्मीरी मुसलमानों के भारत के साथ अपने मुस्लिम–बहुल पड़ोसी पाकिस्तान के साथ इलाके के झगड़े में साथ देने के लिए जिम्मेदार रहा है। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार कुछ और ही सोचती थी। उसने कश्मीरी मुसलमानों को दबाने के लिए आक्रामकता का इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने ही वोटरों को यह साबित करने का फैसला किया कि वह कांग्रेस और यहां तक कि वाजपेयी की भाजपा सरकार के उलट एक मजबूत और ताकतवर सरकार है। ऐसा तरीका शायद ही कभी काम करता है। अगर वहां के लोग भाईचारे की उम्मीद को पसंद नहीं करते हैं तो भारतीय सरकार या कोई भी राज्य हथियारों के बल पर राज नहीं कर सकता। ऐसी जगहों पर आतंकवाद पनपता है। लाल किले में हुए धमाके के कुछ मुख्य साजिशकर्ता साऊथ कश्मीर के पहलगाम से हैं, जहां पहले से बदनाम आई.एस.आई. के प्लान किए गए आतंकी हमले की खबर आई थी। 'ऑप्रेशन सिंदूर' हमारा कामयाब जवाब था। हमारी एयर फोर्स और सपोर्टिंग ग्राऊंड फोर्स ने हमारे पड़ोसी के इलाके में आतंकियों के कई ठिकानों को खत्म करके अपना काम ठीक से किया। बदकिस्मती से, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना जोश रोक नहीं पाए और खुलेआम धमकी दी कि अगर हमारे पड़ोसी ने कभी बॉर्डर पार अपने आतंकी शागिर्दों को भेजने की हिम्मत की तो वे 'ऑप्रेशन सिंदूर' दोहराएंगे। न तो लडने वाले पड़ोसी और न ही दुनिया की बड़ी ताकतें इंडियन सब–कॉन्टिनैंट में कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी के नतीजों को मान पाएंगी। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर दिल्ली में हुए धमाके के बाद, यू.एस. सैक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने शायद बिना कोई कीमती समय बर्बाद किए दिल्ली में अपने समकक्ष से बात की। उन्होंने अगले ही दिन एक बयान जारी कर भारत के 'सोचे–समझे जवाब' और देश के अंदर आतंकी मॉड्यूल की पहचान करने में हमारी कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने देश के कानून के हिसाब से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अपने देश का सपोर्ट जताया। उनके बयान की लाइनों के बीच यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक और 'ऑप्रेशन सिंदूर' के खिलाफ भी सलाह दी। जो मॉड्यूल मिला है, उसने पूरे भारत में और भी कई हमलों की प्लानिंग की थी। इसके जाल हरियाणा और अल–फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत आगे तक फैले हुए थे, जहां यह पनप रहा था। कम से कम एक बड़ा काम तो अभी हो गया है क्योंकि 8 छोटे मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया है लेकिन आने वाले समय में भी लड़ाई जारी रहेगी।

अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। बीते जुलाई माह में कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आदेश के मुताबिक 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। विभाग ने उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के स्थान पर उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स–2025 को लागू करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी। वहीं, स्वीकृत ले–आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वतरू स्वीकृत मान लिया जाएगा। अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) बढ़ा दिया है। वहीं, 45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर निर्माण पर एफएआर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को भी कम किया गया है। कृषि भू–उपयोग में 7–मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय एवं 18 मीटर सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति प्रदान की गई है। भवन की ऊंचाई सीमा से प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। अब चिकित्सालय एवं शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखंड पर बन सकेंगे। शैक्षिक भवनों के खेल के मैदान, खुले क्षेत्र के नियम तय कर दिए गए हैं। ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से घटा कर बिल्टअप (निर्मित) क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर तथा नॉन– बिल्टअप (अनिर्मित) क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर किये जाने तथा बहु–इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को घटाकर 150 वर्ग मीटर किया गया है। साथ ही, पार्किंग को लेकर भी नियम तय कर दिए गए हैं।

खण्ड स्नातक व खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का शेष कार्यक्रम का संशोधित कार्यक्रम जारी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद –झांसी और खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली– मुरादाबाद एवं गोरखपुर–फैजाबाद की निर्वाचक नामावलियों को नये सिरे (De–novo) से तैयार किए जाने को लेकर शेष कार्यक्रम का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य नामावलियों का मुद्रण 27 नवम्बर 2025 तक पूरा किया जाएगा तथा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 02 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक इस दौरान दावे और आपत्तियाँ निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 02 दिसम्बर 2025 से 16 दिसम्बर 2025 तक चलेगी, जिनका निस्तारण 30 दिसम्बर 2025 तक पूरा कर अनुपूरक सूची जारी कर दी जाएगी। अन्तिम निर्वाचक नामावलियाँ 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित होंगी।

पीस एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित की एसआईआर से संबंधित बैठक

संवाददाता

लखनऊ। पीस एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में क्षेत्र की जनता ने भाग लिया और एसआईआर से संबंधित जानकार लोगों के माध्यम से उनको सही प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई। ट्रस्ट के सदर मुर्तजा अली ने बताया कि लखनऊ वासियों की आम जनता के लिए 114 इंसाफ नगर में 30 नवंबर तक यह कैम्प लगाया जाएगा, जिसमें लोगों को मदद की जाएगी। यह कैम्प सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जहां लोगों का फॉर्म भरने और उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रस्ट के संरक्षक खालिद इस्लाम दिलशाद साहब ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को एसआईआर से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाए और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। हम इस कैम्प के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वाहिद ने कहा, यह कैम्प लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमें उम्मीद है कि इस कैम्प के माध्यम से लोगों को एसआईआर से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी और वे अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे।

पांच दिवसीय क्रिप्टोग्राफी फैकल्टी अपडेटेशन कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 'इनोवेशन हब' की ओर से एमई आईटीवाई 'आईएसईए परियोजना' के अंतर्गत "क्रिप्टोग्राफी अनलॉक्ड – फैकल्टी एडिशन" विषय पर पांच दिवसीय फैकल्टी अपडेटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन 17 नवम्बर से 21 नवम्बर तक किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के शिक्षकों को 'क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा' के उभरते क्षेत्रों में उन्नत ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। इस पांच दिवसीय 30 घंटे के कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर लखनऊ विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लेकर प्रतिभागी शिक्षकों को आधुनिक क्रिप्टोग्राफी के मूल सिद्धांतों से लेकर उन्नत अनुप्रयोगों तक का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया।प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्लासिकल सिफर्स से लेकर 'आधुनिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम' तथा हैशिंग और की–एक्सचेंज तकनीकों को विस्तार से बताया गया। पाइथन आधारित प्रायोगिक लैब, वायरशार्क विश्लेषण और ओपेन एसएसएल डेमो' के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉकचेन सुरक्षा, आईओटी क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड सिक्योरिटी और एआई आधारित क्रिप्टोग्राफिक अनुप्रयोगों' पर गहन सत्र हुआ। कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रतिभागी शिक्षकों ने 'कैपस्टोन प्रोजेक्ट', शिक्षण मॉड्यूल तथा लैब एक्सपेरिमेंट तैयार कर प्रस्तुत किए। कुलपति प्रो0 जेपी पाण्डेय के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबकि मार्गदर्शन डीन इनोवेशन प्रो0 बीएन मिश्रा, एसो0 डीन डॉ0 अनुज कुमार शर्मा ने किया। इनोवेशन हब के हेड महीप सिंह एवं मैनेजर वंदना शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं संयोजन किया।

संक्षिप्त

सीएम योगी समेत कई नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी जन्मदिन पर बधाई

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने शुक्रवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दीं। मुख्यमंत्री योगी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' खाते पर बधाई संदेश में कहा, ''उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इसी पोस्ट में उन्होंने कहा, आपका स्नेहिल व्यक्तित्व, मातृवत् संवेदना और समाज सेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्राप्ति हो। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर अपने एक बधाई संदेश में कहा, ''उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर कहा, ''गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त करने वालीं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आनंदीबेन पटेल जुलाई 2019 से उप्र की राज्यपाल हैं। इसके पहले वह मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहीं। वह गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं और उससे पहले वह गुजरात सरकार में मंत्री भी रहीं। उनका जन्म 21 नवंबर, 1941 को गुजरात प्रांत में हुआ।

ऋषि का सद्ज्ञान मानव जीवन का आधार है : उमानन्द शर्मा

संवाददाता

लखनऊ। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत "शेरवुड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग के पास, धरसनिया, बाराबंकी, उ०प्र०" के केन्द्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं० श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का 453वाँ ऋषि वाङ्मय की स्थापना का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुकेश श्रीवास्तव (पुत्र) एवं उर्मिला श्रीवास्तव (पुत्रवधु) ने अपने माता–पिता स्व० सुषमा श्रीवास्तव एवं स्व० कौशल किशोर श्रीवास्तव की स्मृति में संस्थान के पुस्तकालय में युग ऋषि वाङ्मय साहित्य भेंट किये तथा उपस्थित संकाय सदस्यों एवं छात्र–छात्राओं को अखण्ड ज्योति (हिन्दी) पत्रिका भी भेंट किये। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि "ऋषि का सद्ज्ञान मानव जीवन का आधार है।" इस अवसर पर वी०के० श्रीवास्तव एवं संस्थान के निदेशक (सामान्य प्रशासन) सतीश कुमार श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किये। संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ० राज अमित सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रतिनिधि उमानंद शर्मा, देवेन्द्र सिंह, वी०के० श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव एवं संस्थान के निदेशक (सा०प्र०) सतीश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य डॉ० राज अमित सिंह, निदेशक प्रदीप पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर शिवांगी मौर्य, रजिस्ट्रार विजय यादव, संकाय सदस्य एवं छात्र–छात्रायें मौजूद रहे।

आरसीएम की रूपांतरण यात्रा में नवोद्यमियों की सहभागिता, लखनऊ में मिला जबरदस्त जनसमर्थन

संवाददाता

लखनऊ। आरसीएम की राष्ट्रव्यापी रूपांतरण यात्रा के शुभारंभ के बाद से अब तक लाखों नवोद्यमी इससे जुड़ चुके हैं, जो कंपनी की जन–आधारित विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यात्रा का नवीनतम पड़ाव लखनऊ रहा, जहां हजारों नागरिकों ने स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। लखनऊ और इससे पहले आयोजित कई शहरों में लाखों लोगों की भागीदारी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 शहरों की इस यात्रा के 23 दिसंबर 2025 को समापन तक इसकी पहुँच लगभग एक मिलियन लोगों तक हो सकती है। लखनऊ कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने रक्तदान किया और स्वस्थ जीवनशैली व आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी प्राप्त की। लोगों का सामूहिक उत्साह इस बात का प्रमाण था कि वे केवल उपस्थित होने के लिए नहीं, बल्कि निःस्वार्थ योगदान देने के लिए आगे आए–यह दर्शाता है कि यात्रा किस प्रकार लोगों को स्वास्थ्य (जीलं), सेवा (मू) और संस्कार (दांत) के तीन मूल स्तंभों पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। उत्तर प्रदेश आरसीएम की विकास यात्रा में एक विशेष स्थान रखता है। राज्य ने हमेशा आरसीएम की पहलों के प्रति मजबूत जुड़ाव दिखाया है, जो यहां के लोगों के विश्वास और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 16 सितंबर 2025 को रूपांतरण यात्रा की शुरुआत के बाद से अब तक 20,000 से अधिक लोग आरसीएम परिवार से जुड़ चुके हैं, जिससे कंपनी के दो मिलियन से अधिक सक्रिय एसोसिएट बायर्स के नेटवर्क को और मजबूती मिली है। जैसे–जैसे यात्रा अन्य शहरों की ओर अग्रसर है, यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के नेटवर्क का यह विस्तार न केवल सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं, युवाओं और नवोद्यमियों को स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में आरसीएम के प्रयासों को भी प्रतिबिंबित करता है। विशेष रक्तदान शिविर में लोगों की भारी भागीदारी रही, जिससे अब तक यात्रा के दौरान 2,000 से अधिक दाताओं का आंकड़ा पार हो चुका है। कार्यक्रम में नागरिकों को स्वस्थ और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली जन–जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। लखनऊ के लोगों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। हजारों लोग सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल ग्राउंड, कानपुर,हरदोई लिंक रोड, शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के पास, सरोसा, लखनऊ में आयोजित इस आयोजन में शामिल हुए। इस यात्रा का प्रभाव प्रतिभागियों की साझा कहानियों में झलकता है। एक प्रतिभागी ने, जिन्होंने दो दशकों के बाद रक्तदान किया, इसे अत्यंत संतोषजनक अनुभव बताया। एक अन्य प्रतिभागी ने बताया कि चावल की भूसी के तेल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी उनके लिए एक नई सीख थी। कार्यक्रम दो भागों में संपन्न हुआ–सुबह स्वास्थ्य और सेवा से जुड़ी गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जबकि शाम को उत्सव और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया।

खादी महोत्सव का शुभारंभ, ग्रामीण कारीगरों के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिला नया आयाम

स्वरोजगार व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का संकल्प, खादी उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी शुरू

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 दिवसीय 'खादी महोत्सव–2025' का भव्य उद्घाटन किया। मंत्री सचान ने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 160 से अधिक उद्यमियों एवं इकाइयों द्वारा स्थापित स्टॉल में खादी एवं ग्रामोद्योग से निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। खादी को गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा कहा था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्र के रूप में खादी ने आजादी के आंदोलन में पूरे देश को एकजुट किया था। आज वही खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुकी है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि खादी महात्मा गांधी के स्वावलंबन के विचार से जुड़ी हुई है और आज प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता, स्वदेशी, स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत खादी पुनः राष्ट्रीय पहचान की शान बन रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 मंडलों में खादी एवं ग्रामोद्योगी प्रदर्शनियों का आयोजन कर ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वर्ष कराया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। 2025 में 66,640 युवाओं को टूलकिट प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ा गया है। दोना मेकिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, हनी बॉक्स और विद्युत चालित चाक जैसे उपकरण ग्रामीण

आयोजित कुल 20 प्रदर्शनियों में 2000 से अधिक इकाइयों की भागीदारी रही। 44.38 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गयी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्तमान में 3,90,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं चयनित लाभार्थियों को विभिन्न टूलकिट वितरित कर सम्मानित किया गया।इस दौरान प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने कहा कि खादी आधुनिक डिजाइनों और तकनीकों के माध्यम से युवाओं की पहली पसंद बन रही है। फैशन शो एवं निफ्ट जैसी संस्थाओं की सहभागिता से खादी को नया स्वरूप मिल रहा है। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से खादी उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कारीगरों को अधिक आय और पहचान मिल रही है। बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास लगातार मजबूत रहे।लखनऊ वासियों से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक संख्या में महोत्सव में पहुंचकर खादी उत्पादों की खरीदारी करें और ग्रामीण कारीगरों का मनोबल बढ़ाएं। मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे इस आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार कर खादी को बढ़ावा देने में सहयोग करें। कार्यक्रम में विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मंत्री राकेश सचान ने चयनित लाभार्थियों एवं उद्यमियों को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज्य स्तरीय उत्कृष्ट इकाइयों के रूप में मेरठ के दीपक कुमार को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 40,000 रुपये, गोण्डा की ममता को द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 30,000 रुपये तथा हाथरस के संजय सिंह को तृतीय पुरस्कार स्वरूप 20,000 रुपये प्रदान कर सम्मानित किया गया। चयनित पांच लाभार्थियों शशि शुक्ला, पिंकी, उमाकांत, विद्यावती एवं हिन्दराज को दोना मेकिंग मशीन प्रदान की गई, वहीं पॉपकार्न मशीन का वितरण पांच लाभार्थियों सोनी, प्रीती, अर्जुन, किशन कुमार तथा अंकित साहू को किया गया। हनी बॉक्स उपलब्ध कराए जाने हेतु राकेश वर्मा, मीना, शिवशंकर पटेल, अजय वर्मा एवं अनीता वर्मा को चयनित कर उन्हें सम्मानित किया गया। मिट्टी के शिल्पकला कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत चालित चाक भी पांच चयनित लाभार्थियों जियाउल हक, शिवकुमार, अनुराग प्रजापति, सुरेन्द्र कुमार तथा पीयूष प्रजापति को प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पगमिल के लिए चयनित एकमात्र लाभार्थी पप्पी को उपकरण प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

बनारस में हुआ राजनीतिक डेमोलिशन

दालमंडी को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश

संवाददाता

लखनऊ। वाराणसी के दालमंडी में मकान तोड़े जाने और चौड़ीकरण परियोजना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला।उन्होंने इसे ष्राजनीतिक डेमोलिशनष् करार देते हुए कहा कि दालमंडी में भाजपा कभी जीतती नहीं, इसलिए यहां बदले की भावना से तोड़फोड़ कराई जा रही है। बनारस के कई बूथों का प्रिंट दिखाते हुए अखिलेश ने कहा कि बूथ देखिए तो दालमंडी में कभी भाजपा को वोट नहीं मिले। यहां वोट नहीं मिलते इसलिए यहां तोड़फोड़ हो रही है।अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले दूसरों को दुख–तकलीफ देने वाले लोग हैं। भाजपा को लोगों की दुकानें छीनने का अधिकार किसने दिया है। नकारात्मक सोच वाले कुदरत के फैसले से बच कर रहें। किसी दिन राजनीति उनकी ढह जाएगी। लखनऊ में हमने देखा कि अकबरनगर को पूरा धराशायी कर दिया। लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई लोगों के मकान दुकान को अवैध घोषित करके कुछ हासिल नहीं होने देंगे। भाजपा वाले नक्शा पास कराने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है क्या? इस सरकार ने अपनी जमीन अधिगृहित किया तो खूब मुआवजा लिया। मनचाहा मुआवजा लिया गया। इस बात को सदन में भी कहा था। जैसा मुआवजा आपने अपने जमीन का लिया, इन्हें भी वैसा ही मुआवजा दे दो। अखिलेश ने दावा किया कि सपा सरकार में बनारस के लिए मेट्रो का डीपीआर तैयार था। हमने लखनऊ–कानपुर में मेट्रो चला दी, अगर बनारस में यह लोग मेट्रो बना देते तो दालमंडी को तोड़ना नहीं पड़ता।दालमंडी में तोड़फोड़ को अंजाम दे रहे अधिकारियों को इशारों में चेताते हुए कहा कि महाराजगंज को याद कीजिए, क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों से वसूली की जाए। यहां भी यही होगा, आज नहीं तो कल होगा। सब नोट हो रहा है। कुछ हमारे यहां नोट हुआ है। कुछ कुदरत के पास नोट हो रहा है। कहा कि हम लोगों ने फैसला ले लिया, इनके लिए कुछ करेंगे।उन्होंने योगी सरकार को अभी तक की सबसे करप्ट सरकार बताया और कहा कि यह सरकार जाने वाली है।

राष्ट्रीय लोकदल ने शुरू कर दी पंचायत व 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी

संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोक दल पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से अपने संगठन को विस्तार देने, जनाधार को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से जोड़ने के व्यापक अभियान में जुटा हुआ है। पार्टी का उद्देश्य प्रदेश के हर जिले, हर तहसील और हर ग्राम पंचायत तक अपनी पहुँच बनाकर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरना है। आगामी पंचायत चुनावों तथा उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल, एनडीए गठबंधन के साथ पूर्ण शक्ति, रणनीति और सशक्त संगठन के बल पर चुनावी तैयारी में जुट गया है। राष्ट्रीय लोक दल अब केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर अपने जनाधार को सुदृढ़ कर रहा है। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार सम्मेलन, सभाएं, संवाद कार्यक्रम तथा संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी तथा प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय के नेतृत्व में बांदा, प्रयागराज, बस्ती, कानपुर, श्रावस्ती, हरदोई, गोरखपुर, कुशीनगर, झांसी, बरेली, गोंडा, उन्नाव, फैजाबाद, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, वाराणसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटाह, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, कौशाम्बी सहित प्रदेश के दर्जनों जिलों में विशाल सम्मेलन आयोजित हुए हैं। इन आयोजनों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं, किसानों, नौजवानों एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी का संदेश तेजी से जन–जन तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय लोक दल का उद्देश्य केवल चुनावी विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और किसान–मजदूर आधारित राजनीति को सशक्त करना है। मथुरा कोसिकला में पार्टी के ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक दल किसानों, मजदूरों, पिछड़े वर्गों, युवाओं और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर समतामूलक राजनीति को मजबूत करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अधिवेशन में पारित प्रस्तावों ने पार्टी की भविष्य की दिशा, नीतिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। राष्ट्रीय लोक दल का सदस्यता अभियान 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती तक चला।

प्रदेशवासियों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्य : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ 25 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हुए शामिल

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित "छत्तीसगढ़ 25 साल बेमिसाल" कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 25 वर्ष की स्वर्णिम विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बस्तर सहित पूरे प्रदेश में विकास में बाधक नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने से सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में किए जा रहे प्रयासों से नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और बस्तर अपने मूल स्वरूप में भयमुक्त होकर प्रदेश के विकास में बेहतर भागीदारी देगा। साय ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के माध्यम से बस्तर की संस्कृति और प्रतिभा को दुनिया ने देखा है। बस्तर में शांति, समृद्धि और खुशहाली के नए युग का आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी दृढ़ता से लागू है। पूर्व में जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुए, उस पर कड़ा प्रहार किया गया है, जिसका परिणाम भी सभी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने भूखमरी जैसे अभिशाप को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे, जिसके तहत गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध कराया गया। साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को आज आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लगभग सभी गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण 'चरण पादुका योजना' को भी पुनः प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने नई उद्योग नीति के आकर्षक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। अब तक राज्य सरकार को पौने आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे आने वाले वर्षों में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी अलोक सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

केंद्र का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : नीरज मित्तल बने पेट्रोलियम सचिव, कई मंत्रालयों में शीर्ष स्तर पर बदलाव

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत वरिष्ठ नौकरशाह नीरज मित्तल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी मित्तल फिलहाल दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे पंकज जैन की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। इन पदों में भी किए गए फेरबदल औषधि विभाग के सचिव अमित अग्रवाल को मित्तल के स्थान पर दूरसंचार सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी अग्रवाल के स्थान पर फार्मास्यूटिकल्स सचिव होंगे। 20 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यटन सचिव वी विद्यावती अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सचिव होंगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीवत्स कृष्णा, जो वर्तमान में अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं, नए पर्यटन सचिव होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव अतीश चंद्रा को कृषि व किसान कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। अधिकारी 28 फरवरी, 2026 को देवेश चतुर्वेदी की सेवानिवृत्ति के बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग में सचिव का पदभार संभालेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वर्तमान में विधि मामलों के विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत अंजू राठी राणा को भारत के 23वें विधि आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विधि व न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि का कार्यकाल 9 जनवरी, 2026 से 31 जुलाई, 2028 तक मतलब उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। एसीसी ने मणि को विधि मामलों के विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को भी मंजूरी दे दी है।

कृषि मंत्री बोले- बीमा योजना में जंगली जानवरों और जलभराव से होने वाला नुकसान भी शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अब दो तरह के नुकसान भी कवर किए जाएंगे, जिनकी किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। जंगली जानवरों और जलभराव से बर्बाद हुई फसलों पर मिलेगा मुआवजा चौहान ने कहा कि अब जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए गए नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही अत्यधिक बारिश से आई बाढ़ या जलभराव के कारण फसल को हुए नुकसान को भी योजना में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जंगली जानवर फसल खराब करते हैं, तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। अगर भारी बारिश से जलभराव होता है और फसल बर्बाद होती है, तो भी नुकसान की भरपाई की जाएगी।

'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' से सम्मानित होगे कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

भारत स्काउट्स एंड गाइड का सबसे बड़ा सम्मान है 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड'
आगामी 26 नवम्बर को उत्तर प्रदेश राजभवन में दिया जायेगा सम्मान

बीएनई

देहरादून। भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री व डॉ. धन सिंह रावत को स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार आगामी 26 नवम्बर को उत्तर प्रदेश राजभवन, लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा दिया जाने वाला 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' देश में स्काउट एंड गाइड आंदोलन का सबसे बड़ा सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संगठन के विस्तार, चरित्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण हेतु विशेष योगदान दिया हो। डॉ. रावत को यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तराखण्ड में स्काउट–गाइड आंदोलन को मजबूत बनाने, इसे व्यापक स्तर पर लागू करने तथा युवाओं में अनुशासन, एकता और देशभक्ति का भाव विकसित करने के उद्देश्य से किये गये उनके प्रयासों के लिये दिया जा रहा है। अपने कार्यकाल में डॉ. रावत ने प्रदेश के सभी निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थानों में स्काउट एंड गाइड गतिविधियों को अनिवार्य रूप से लागू करने, साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में इसकी इकाइयां स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये। उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स की संख्या को बढ़ाकर दो लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संगठन के विस्तार को नई दिशा दी। इसके अतिरिक्त डॉ. रावत ने स्काउट एंड गाइड के माध्यम से साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, राज्य में विभिन्न सामाजिक सरोकार पर आधारित अभियानों के संचालन तथा युवाओं को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने में विशेष पहल की। सिल्वर एलीफेंट अवार्ड के लिए चुने जाने पर डॉ. धन सिंह रावत ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संस्था देश के असंख्य युवाओं को एक जिम्मेदार, सक्षम और संवेदनशील नागरिक के रूप में तैयार करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि स्काउट–गाइड गतिविधियाँ विद्यार्थियों में शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षमताओं के विकास के साथ–साथ विश्वव्यापी भाईचारे की भावना को भी सुदृढ़ करती हैं।

'वन्दे मातरम्' के सामुहिक गायन को जुटेंगे 20 लाख छात्रः डॉ. धन सिंह रावत

संविधान दिवस पर सभी शिक्षण संस्थानों में आयोजित होगा कार्यक्रम
सामुहिक गायन कार्यक्रम में राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी करेंगे प्रतिभाग

बीएनई

देहरादून। 'संविधान दिवस' के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र गीत 'वन्दे मातरम' का सामुहिक गायन किया जायेगा। जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र–छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले सामुहिक गायन कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित सभी महानुभाव व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर सम्बंधित विभागों के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रदेशभर समस्त राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों में आगामी 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' को वृहद स्तर पर मनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस महत्पूर्ण अवसर पर 20 लाख से अधिक छात्र–छात्राएं, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड व एनसीसी गाइड प्रातः 9:30 बजे एक साथ राष्ट्र गीत 'वन्दे मातरम्' का सामुहिक गायन करेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों में आयोजित होने वाले सामुहिक गायन कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा उक्त कार्यक्रम में स्वाधीनता सेनानी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों सहित जिलों के प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सरकार में दर्जा राज्य मंत्रियों, नगर निगमों के महापौरों, जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर निकायों के अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को 'वन्दे मातरम्' के सामुहिक गायन कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग के साथ ही फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये, जिनको जियोटैग भी किया जायेगा। उन्होंने आयोजन संबंधी उत्कृष्ट वीडियो, फोटो व विशिष्ट उपलब्धि को www.vandemataram150.in वेबसाइट व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड़ करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये उन्होंने सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को ब्लॉक व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर आवश्यक समन्वय स्थापित के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद युवा पीढ़ी में भारतीय संविधान व राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और राष्ट्रभावना को मजबूत करना है, साथ ही राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व राष्ट्रीय एकता की भावना को भी विकसित करना है। बैठक में सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा डॉ. रणजीत सिन्हा, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक गैरोला, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विक्रम यादव, निदेशक उच्च शिक्षा वी. एन. खाली, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अजय आर्य, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक संस्कृत शिक्षा कंचन देवराड़ी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दुनिया के शीर्ष-100 बैंकों में जल्द शामिल होगे और भारतीय बैंक; अभी सिर्फ SBI और HDFC ही शामिल

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को उम्मीद है कि आर्थिक विस्तार एवं बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि की रफ्तार को देखते हुए देश के और बैंक भी जल्द ही दुनिया के शीर्ष–100 बैंकों की सूची में शामिल होंगे। वर्तमान में सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और एचडीएफसी बैंक ही दुनिया के शीर्ष–100 बैंकों की सूची में शामिल हैं। ये दोनों बैंक क्रमशः 43वें और 73वें स्थान पर हैं। मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में वीकेआरवी राव स्मृति व्याख्यान के बाद छात्रों से बातचीत में कहा, आरबीआई भारत के कई बड़े बैंकों को वैश्विक सूची में शामिल नहीं कर सकता, जबकि इसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कई बैंक हैं। जिस रफ्तार से वे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यह सिर्फ समय की बात है कि दुनिया के शीर्ष–100 बैंकों में हमारे कई बैंक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में कहा था, देश को बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत है। यह नए बैंक बनाने से नहीं हो सकता है। विलय भी एक रास्ता हो सकता है। इस संबंध में आरबीआई और वित्तीय संस्थानों से बातचीत जारी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, तेज रफ्तार से बढ़ रहे कई सरकारी व निजी क्षेत्र के बैंक वित्त मंत्री भी दे चुकी हैं वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत पर जोर 26 फीसदी बढ़ा पीएसबी का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को वित्त वर्ष 2024–25 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये का कुल मुनाफा हुआ था। यह एक साल पहले की तुलना में 26 फीसदी अधिक है। 2023–24 के दौरान 12 सरकारी बैंकों ने कुल 1.41 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया था। रुपये के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं डॉलर की मांग से आ रही गिरावट आरबीआई गवर्नर ने कहा, केंद्रीय बैंक ने रुपये के लिए किसी भी स्तर का लक्ष्य नहीं बनाया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा में हाल में आई गिरावट की वजह डॉलर की मांग में तेजी है। मल्होत्रा ने कहा, भारतीय रुपये का हालिया अवमूल्यन व्यापारिक गतिविधियों और अमेरिकी टैरिफ के कारण है। हम किसी स्तर को लक्ष्य नहीं बनाते। रुपये में गिरावट क्यों आ रही है? ऐसा मांग के कारण है। डॉलर की मांग है और यह बढ़ती है, तो रुपये में गिरावट आती है। आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का काफी अच्छा भंडार है। बाह्य क्षेत्र को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की उम्मीदें कायम, लक्ष्य सेन ने आयुष को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

सिडनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने अपने हमवतन और युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी को सीधे सेटों में 23–21, 21–11 से पराजित किया। यह मुकाबला शुक्रवार को सिडनी में खेला गया। सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने इस साल पहले भी हॉन्गकॉन्ग ओपन में शेट्टी को इसी चरण में हराया था। इस जीत ने लक्ष्य की लय और आत्मविश्वास दोनों को मजबूती दी है, खासकर तब जब वे इस सत्र में अभी तक कोई खिताब नहीं जीत सके हैं। पहला गेम : रोमांचक मुकाबला पहला गेम बेहद कड़ा और उतार–चढ़ाव भरा रहा। शुरुआत में लक्ष्य पीछे चल रहे थे और आयुष शेट्टी 9–6 की बढ़त लिए हुए थे, लेकिन लक्ष्य ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 4 अंक लेकर 13–10 की बढ़त बना ली। इसके बावजूद शेट्टी ने हार नहीं मानी और लगातार रैलियों में लय बनाए रखी। स्कोर 21–21 पर बराबरी पर था, लेकिन आख़िरकार अनुभव और संयम ने लक्ष्य सेन को पहला गेम 23–21 से दिला दिया। दूसरा गेमरू लक्ष्य का दबदबा दूसरे गेम में लक्ष्य का आत्मविश्वास पूरी तरह नजर आया। उन्होंने शुरुआत से ही 6–1 की बढ़त बना ली और फिर शेट्टी मैच की रफ्तार पकड़ नहीं पाए। जैसे–जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, लक्ष्य और मजबूती से खेलते गए और स्कोर 15–7 तक पहुंच गया। अंत में लक्ष्य सेन ने 21–11 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम किया।

अजय के साथ दोस्ती का नहीं यह रिश्ता रखती हैं रकुल प्रीत, दो फिल्मों में कर चुकी हैं अभिनेता के साथ रोमांस

एजेंसी

रकुल प्रीत सिंह हाल ही में अजय देवगन के साथ फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आईं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ठीक–ठाक कमाई कर रही है। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि वह इंडस्ट्री में नई नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें अजय देवगन के मुकाबले बहुत ही कम अनुभव है। उन्होंने बताया है कि वह अजय देवगन के साथ दोस्ती का रिश्ता क्यों नहीं रख सकती। अजय के साथ दोस्ती का रिश्ता नहीं रख सकती रकुल बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में रकुल प्रीत सिंह ने बताया मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता नहीं रख सकती। मेरा उनका रिश्ता सम्मान वाला है। मेरे लिए वह अभी भी अजय देवगन हैं। वह सीनियर अभिनेता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अजय देवगन को सर मानती हूं। मैं अजय देवगन को सर की तरह क्यों नहीं रह सकती, इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा श्जो आपकी उम्र के या आपसे कम उम्र के एक्टर होते हैं, वह आपके दोस्त बन जाते हैं। अजय देवगन को मैं सर मानती हूं। मैं अपने आपको इंडस्ट्री में नई नहीं मानती, फिर भी मेरा उनसे कम अनुभव है। दे दे प्यार दे 2 की कमाई में आई मामूली गिरावट, जानें बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हक और कांथा का हाल दे दे प्यार दे 2 के बारे में अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म दे दे प्यार दे 2 में रकुल प्रीत और अजय देवगन के अलावा आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी और अर्जुन पांचाल जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज हुई थी। इसमें बड़ी उम्र के पुरुष का छोटी उम्र की लड़की के साथ रोमांस दिखाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक 51.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743